हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान - केशव प्रसाद मौर्य

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

❑ प्रतापगढ़ के तुलसीसदन में आपातकाल से सम्बन्धित चित्र प्रदर्शनी का उप मुख्यमंत्री ने फीता काटकर किया उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ पुलिस लाइन हेलीपैड पहुँचने पर मार्च पास्ट की सलामी ली। हेलीपैड पर उप मुख्यमंत्री का विधायक सदर राजेन्द्र प्रसाद मौर्य, विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, आशीष श्रीवस्ताव, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता, पूर्व विधायक धीरज ओझा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि विनोद पाण्डेय, गिरधारी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आदित्य प्रजापति ने बुके देकर स्वागत किया। उसके उपरान्त उप मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन परिसर में ''एक पेड़ माँ के नाम'' से आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधरोपित किये। उसके उपरान्त उप मुख्यमंत्री ने संई काम्प्लेक्स सभागार में पत्रकार बन्धुओं के साथ आपातकाल दिवस के अवसर पर प्रेसवार्ता की।

50वें आपातकाल दिवस के अवसर पर तुलसीसदन (हादीहाल) में आयोजित कार्यक्रम का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्र्यापण व दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस दौरान आपातकाल लगाये जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तुलसीसदन में आपातकाल से सम्बन्धित चित्र प्रदर्शनी लगायी जिसका उप मुख्यमंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया एवं प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्बोधित करते हुये कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों के सम्मान में 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपातकाल दिवस मनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को भारत पर आपातकाल थोप दिया गया था। उन्होंने आपातकाल के दौरान पैदा हुयी परिस्थितियों व कठिनाइयों के बारे मे विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होने कहा कि हमारा संविधान स्वतंत्र और अमर है, जिस पर हमे गर्व है। हम अपने संविधान की हत्या नहीं होने देगें। कहा कि

जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिये बनाया था,उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिये गये थे। आपातकाल के बुरे दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होने कहा कि हम लोकतांत्रिक की पवित्र भावना को मजबूत करने के लिये हर सम्भव प्रयास करें। उन्होने कहा कि 25 जून जैसा दिन हमारी सरकार आने नहीं देगी। वर्ष 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बने है, वह संविधान की रक्षा कर रहे है और वर्ष 2017 में जब से डबल इंजन की सरकार बनी, तब से काफी बदलाव हुये है। आज हमारी सरकार शहरों में 24 घंटे व गांवों में 18 घंटे बिजली दे रही है, यदि कहीं पर ट्रान्सफार्मर जल जाता है, तो तत्काल ट्रान्सफार्मर बदला जाता है। उन्होने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के साथ कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि मा0प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें हर नौजवान को नौकरी, हर गरीब को घर मिल सके। डबल इंजन की सरकार बनाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज देश में महिलाओं की हर क्षेत्र मे भागीदारी है। उन्होने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से विधानसभा व लोकसभा 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया।

हाई वैल्यू और प्रसंस्करण वाली फसलों से उद्यान विभाग बढ़ायेगा निर्यात

लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान निदेशालय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर इकोनामी के स्तर पर ले जाने के लिए विभाग के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में किए जा रहे प्रयासों तथा अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की।

समीक्षा बैठक में उद्यान मंत्री के समक्ष औद्यानिक फसलों एवं प्रसंस्.त उत्पादों के निर्यात को बढ़ाए के क्रम में लैंड-लाक्ड राज्यों द्वारा निर्यात किए जा रहे औद्यानिक फसलों एवं उत्पादों पर अध्ययन कर डिलाइट इंडिया द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। मंत्री ने डिलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक उत्पादवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उद्यान मंत्री ने प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पौध व रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निष्प्रयोज्य प्रक्षेत्रों पर पीपीपी माडल पर औद्यानिक सीड पार्क विकसित किए जाने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने हेतु टीम का गठन किये जाने के निर्देश दिये ताकि योजनाओं, उन्नत तकनीक, बागवानी से संबंधित एडवाइजरी आदि किसानों को आसानी उपलब्ध हो सके।

मंत्री श्री सिंह ने कृषकों की आय बढ़ाने के लिए हाई वैल्यू, निर्यातोन्मुखी तथा प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने पर फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ाने हेतु औद्यानिक विशेषज्ञों की टीम को देश-विदेश में निर्यात के नये अवसर तलाशने के निर्देश दिये।

बैठक के उपरान्त उद्यान मंत्री ने उद्यान भवन परिसर में बनाई गई औषधीय वाटिका का भ्रमण किया गया। इस औषधीय वाटिका में 31 किस्म के औषधीय पौधे रोपित हैं।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीणा, निदेशक बीपी राम, संयुक्त निदेशक सर्वेश कुमार एवं राजीव वर्मा सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना

इस अंक के साथ निम्नलिखित बैंकों की बैलेन्सशीट प्रकाशित की जा रही हैं-

1. मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक लि0, मुरादाबाद
2. जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी।

'वंदे मातरम्' माँ भारती के प्रति अटूट प्रेम, को दर्शाता है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज गौरव अनुभूति आयोजन समिति द्वारा प्रयागराज स्थित शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सर्किट हाउस में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के अमर रचयिता युग मनीषी श्रद्धेय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि 'वंदे मातरम्' माँ भारती के प्रति अटूट प्रेम, बलिदान और आत्मसम्मान का ऐसा मंत्र है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारियों को राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेरित किया और आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना को बलवती बनाता है। कहा कि श्रद्धेय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को 'वन्दे मातरम्' के रूप में राष्ट्रभक्ति का स्वर देकर एकजुट किया तथा उनकी प्रसिद्ध कृति 'आनंदमठ' ने जन-जन में राष्ट्रप्रेम की अलख जगाने का कार्य किया।

इस अवसर पर अवधेश गुप्ता, विधायक गुरू प्रसाद मौर्य, श्रीमती निर्मला पासवान, संजय गुप्ता, राजेश शुक्ला, जनप्रतिनिधियो, समाजसेवियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

तकनीक आधारित शिक्षा से ही युवा बनेंगे आत्मनिर्भर रू कपिल देव अग्रवाल

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रभारी मंत्री हापुड़/बिजनौर कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुलतानपुर का दौरा कर संस्थान की गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को तकनीक और परिश्रम को जीवन का आधार बनाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

निरीक्षण के दौरान कौशल विकास मंत्री ने टी.टी.एल. योजना के अन्तर्गत संचालित इण्डस्ट्रियल रोबोटिक्स एवं डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन व्यवसाय के प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार रोबोटिक आर्म का प्रदर्शन देखा और छात्रों के नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीक आधारित ज्ञान का है। हमारे युवा अगर हुनर और तकनीकी दक्षता से लैस होंगे तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संस्थान में संचालित टी.टी.एल., जी.आई.टी.आई., कौशल विकास मिशन एवं आई.टी.ओ.टी. से जुड़े प्रशिक्षार्थियों को एक साथ संबोधित करते हुए मंत्री अग्रवाल ने निर्देशित किया कि प्रशिक्षण के साथ ही उद्योगों से जुड़ाव की प्रक्रिया और तेज की जाए ताकि युवा सीधे रोजगार से जुड़ सकें। हर संस्थान में टेक्नोलाजी आधारित व्यवसायों को प्राथमिकता दी जाए। प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। उद्योग-शिक्षा समन्वय मंच के माध्यम से स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार कोर्स संरचना में संशोधन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए हर संभव संसाधन और प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को चाहिए कि वे न केवल नौकरी पाने बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से औरों को रोजगार देने की दिशा में भी सोचें।

लखनऊ बनेगा देश दुनिया का पहला जीरो वेस्ट शहर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी और लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने लखनऊ की मोहान रोड़ स्थित शिवरी कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचकर वहां पर लखनऊ को देश दुनिया का पहला जीरो वेस्ट शहर बनाने के लिए कूड़ा प्रोसेसिंग की 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाली तीसरी यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन किया और बटन दबाकर प्लांट को चालू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ और कचरे से कंचन बनाने के संकल्प को नगर विकास विभाग साकार कर रहा है, यहां पर अब 700 मीट्रिक टन क्षमता का यह तीसरा प्लांट शुरू होने से अब 2100 मीट्रिक टन कूड़े का प्रतिदिन निस्तारण हो सकेगा और लखनऊ से प्रतिदिन निकलने वाला 2000 मीट्रिक टन कूड़ा रोजाना निस्तारित किया जा सकेगा। इस ऐतिहासिक पहल से लखनऊ को देश और दुनिया का पहला जीरो वेस्ट शहर बनाने में सफलता मिलेगी।

सहकारिता

संरक्षक
योगेश कुमार (आईए.एस.)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0

श्रीकान्त गोस्वामी
प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह
महाप्रबन्धक

स्वत्वाधिकारी, यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रकाशक, मुद्रक सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस, 14, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ, उ0प्र0 से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक-सुनील कुमार दिवाकर
फोन : 0522-4004577 (का.)
मोबाइल : 9415094114
ईमेल : sahkarita@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

आर0 एन0 आई0 नं0 : 25008/72
डाक पंजी0 सं0 - GPO- LW/NP-178/2024-26

सहकारिता

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

वर्ष : 53 अंक : 40 (हिन्दी साप्ताहिक) लखनऊ-वृहस्पतिवार 03 जुलाई, 2025 से 09 जुलाई, 2025 पृष्ठ-4 वार्षिक 150.00 रूपया मात्र एक प्रति 3.00 रूपया

उ0प्र0 के दुग्ध क्षेत्र को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त और किसानों के लिए लाभकारी बनाने की दिशा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण

दुग्ध विकास के क्षेत्र में उ0प्र0 में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर उनकी उपस्थिति में प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0) द्वारा संचालित तीन डेयरी प्लाण्ट (कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज) तथा अम्बेडकरनगर स्थित पशु आहार निर्माणशाला के संचालन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन0डी0डी0बी0) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) का आदान-प्रदान सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के दुग्ध क्षेत्र को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सशक्त और किसानों के लिए लाभकारी बनाने की दिशा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एन0डी0डी0बी0 को संचालन सौंपे जाने से इन इकाइयों में तकनीकी दक्षता, पारदर्शिता और व्यावसायिकता के नए मानक स्थापित होंगे, साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान, बेहतर मूल्य और स्थायी विपणन की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। एन0डी0डी0बी0 जैसे दक्ष एवं अनुभवी संस्थान को संचालन सौंपे जाने से इन इकाइयों में तकनीकी कुशलता,

व्यावसायिक पारदर्शिता और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पशुधन सम्पदा और दुग्ध उत्पादन की विशाल क्षमता को यदि नियोजित और वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाए, तो उत्तर प्रदेश न केवल देश का अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य बन सकता है, बल्कि वैश्विक डेयरी मानचित्र पर भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकता है। एन0डी0डी0बी0 के साथ यह एम0ओ0यू0 उसी दिशा में एक ठोस, दूरदर्शी और व्यवहारिक कदम है।

सहकारी बैंक बी-पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराएं ऋण : जेपीएस राठौर

लखनऊ। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर प्रदेश जे0पी0एस0 राठौर द्वारा वाराणसी में सहकारिता विभाग के समस्त अनुभाग के मंडल स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता वाराणसी मंडल वाराणसी श्रीमती सोमी सिंह द्वारा मंत्री को बुके एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया।

मंत्री द्वारा जिला सहकारी बैंकों के सभी सी0ई0ओ0 को बैंक की उपलब्धियों में गिरावट पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए चेतावनी दी गई एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति करते हुए बी पैक्सो के माध्यम से ही कृषकों को अल्पकालीन ऋण वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंत्री द्वारा समस्त सी0ई0ओ0 जिला सहकारी बैंक को निर्देशित किया गया कि खरीफ अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में उर्वरक की आपूर्ति एवं प्रदायकर्ताओ के भुगतान हेतु 30 जून तक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। सभी बी पैक्सो से ऋण सीमा तैयार कराकर समय से स्वीकृत करा लें।

सहकारिता मंत्री द्वारा पैक्सफेड, लैकफेड एवं एस0डब्ल्यू0सी0 के एक्सियन को पैक्स गोदाम की गुणवत्ता एवं सुंदरता का ध्यान रखते हुए निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए गए साथ ही चेतावनी भी दी गई कि किसी प्रकार की शिकायत पर जांच कराए जाने पर भवन की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।

मंत्री द्वारा पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0 के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक को निर्देश दिए गए कि खरीद धान का सी0एम0आर0 प्रत्येक दशा में 30 जून तक पूर्ण करा लें। श्री राठौर समीक्षा बैठक में बताया गया कि नए गठित पैक्सों के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से एक लाख रूपए की वित्तीय सहायता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु एक लाख रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री द्वारा समस्त ए0आर0 को निर्देशित किया गया कि संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर डी0सी0डी0सी0 की बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित कराकर समितियों को भूमि आवंटित कराएं। साथ ही मंत्री द्वारा समस्त ए0आर0 को निर्देशित किया गया कि जनपद की मरम्मत योग्य प्रत्येक समितियों का प्राथमिकता के आधार पर सूची एवं प्राक्लन तैयार करवा कर एक सप्ताह के अंदर आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय को उपलब्ध कराए, ताकि अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र कराई जा सके।

उपायुक्त श्रीमती सोमी सिंह द्वारा मंत्री को अवगत कराया गया कि "सहकार से समृद्धि योजना" के अंतर्गत वाराणसी जनपद में 6 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित कराये गये हैं। जन औषधि केंद्र संचालन में प्रदेश में दूसरा स्थान है, जिस पर मंत्री द्वारा खुशी जाहिर की गई। मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को दीर्घकालीन ऋण वितरण एवं वसूली की खराब स्थिति पर फटकार लगाई गई साथ ही निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण एवं वसूली में तेजी लाएं, अन्यथा की स्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

योगेश कुमार ने ग्रहण किया आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता का कार्यभार

योगेश कुमार आईएएस द्वारा आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। श्री कुमार 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

41 साल बाद फिर से गूंजी अंतरिक्ष में भारत की आवाज

– मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

❑ अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दी बधाई

लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ स्थित भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के आवास पर पहुंचकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए उड़ान भरने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शुभांशु शुक्ला की यह ऐतिहासिक उपलब्धि उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से देश के युवाओं को विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा बिष्ट यादव एवं लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के विधायक डा0 नीरज बोरा भी उपस्थित रहे। सभी ने श्री शुभांशु शुक्ला के परिजनों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

संपादकीय

कृषि : भारत की जीवनरेखा

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 60फ जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल खाद्यान्न का स्रोत है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। गांवों की आजीविका, देश की खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा कृषि से ही आता है। लेकिन आज भी यह क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है ह जैसे जलवायु परिवर्तन, भूमि की उर्वरता में गिरावट, किसानों की आय में असमानता और बाजार व्यवस्था की जटिलताएं।

भारत में कृषि केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। यह समाज के हर वर्ग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ कृषि से संबद्ध उद्योग : जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, रेशम उद्योग आदि भी रोजगार और आय के बड़े स्रोत हैं। गेहूं, धान, दालें, गन्ना, कपास, और बागवानी फसलें भारत को वैश्विक कृषि उत्पादों के नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हैं।

कृषि क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी उल्लेखनीय है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें गिरावट आई है, परंतु यह अब भी करोड़ों लोगों की रोज़ी-रोटी का जरिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि, उपभोक्ता मांग, और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान की वजह से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके समाधान हेतु जल-संरक्षण तकनीकों, सूखा प्रतिरोधी फसलों और मौसम आधारित खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निरंतर भूमि का दोहन, रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग और अवैज्ञानिक खेती ने मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाया है। जैविक खेती, मिश्रित खेती और शून्य बजट खेती जैसे नवाचार अपनाने की आवश्यकता है।

किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। बिचौलियों की भूमिका, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की पहुंच में कमी और भंडारण की असुविधाएं किसान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं। इसके समाधान के लिए डिजिटल मंडियां, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और ई-नाम जैसी पहलें महत्वपूर्ण हैं।

अधिकांश किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहते हैं। आधुनिक तकनीक, कृषि अनुसंधान, मशीनरी और वैज्ञानिक विधियों तक किसानों की पहुंच बढ़ानी होगी।

भारत सरकार ने कृषि सुधारों के तहत कई योजनाएं शुरू की हैं : जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, जोखिम को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना है।

भविष्य में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, कृषि शिक्षा का प्रसार करना, महिला एवं युवा किसानों की भागीदारी को बढ़ाना और कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा। ❑

खरपतवारनाशी पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रही सरकार

❑ अधिक पैदावार के लिए खरीफ फसलों को खरपतवार से बचाएं किसान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है प्रदेश में खरीफ मौसम में लगभग 132 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों की बुवाई की जाती है। खरीफ मौसम में अधिक वर्षा के कारण पौधों की बढ़वार अधिक होती है। विश्व में लगभग तीन लाख से अधिक पौधों की प्रजातियाँ मानव एवं पशुओं के लिए आर्थिक एवं चारे के महत्व की हैं। इनसे वांछित फसल के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के पौधे, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, भी उग जाते हैं। खरपतवारों के प्रबंधन हेतु उनकी जानकारी एवं पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। इनकी मुख्य रूप से तीन श्रेणियाँ हैं, जिनका प्रबंधन उनके जीवन चक्र, पत्तियों के आकार एवं विषम परिस्थितियों में उनके अंकुरण तथा पादप वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। खरपतवारों का अध्ययन मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें संकरी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तथा मोथा वर्गीय खरपतवार शामिल हैं। कृषि उत्पादों की वार्षिक हानि में खरपतवारों द्वारा लगभग 32-35 प्रतिशत, कीटों द्वारा 27 प्रतिशत, पादप रोगों द्वारा 18-20 प्रतिशत तथा अन्य कारकों द्वारा 05 प्रतिशत हानि होती है।

खरपतवारों से होने वाली हानियाँ

फसलों पर खरपतवारों के कारण उनकी वृद्धि, जीवन चक्र एवं उपज पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कृषकों द्वारा अपनी फसलों में खरपतवारों का समय से नियंत्रण सदैव लाभकारी होता है, जिससे खरपतवार एवं फसलों के बीच पानी, पोषक तत्व, स्थान, हवा एवं प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा न हो सके और अंततः फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो।

खरपतवार नियंत्रण की तकनीकें

खरीफ फसलों में समय से खरपतवार का नियंत्रण कृषकों के हित में तथा अच्छी उपज प्राप्त करने का सही उपाय है, जिसके लिए शस्य क्रियाओं का समुचित प्रयोग किया जाना कृषक हित में है जैसे-गर्मी में मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई, फसल चक्र अपनाना, हरी खाद का प्रयोग, पाड्लिंग आदि। खरपतवार का प्रबंधन कृषक एवं पर्यावरण दोनों के हित में रहता है। साथ ही आवश्यकतानुसार मशीनों/यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें खुरपी, हो, वीडर, मल्चर आदि के माध्यम से खरपतवारों के अंकुरण एवं वृद्धि में अवरोध पैदा कर खरपतवार को कम किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त उपाय कारगर न हों तो कृषि रक्षा रसायन/खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से उचित होगा। यह अधिक क्षेत्रफल में कृषि फसलों हेतु लाभकारी एवं ग्राह्य भी है। परंतु इनका सही समय एवं मात्रा में ही प्रयोग मृदा एवं मानव स्वास्थ्य हेतु लाभकारी है। खरीफ की मुख्य फसलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत खरपतवारनाशी का विवरण:

1. धान फसल

धान की सीधी बुवाई (डी.एस.आर.) में खरपतवार नियंत्रण : खरपतवार का प्रबंधन धान की सीधी बुवाई (डी.एस.आर.) में एक मुख्य समस्या है, जिसके निदान के लिए मुख्य खरपतवारनाशी पेन्डीमेथालिन 30 ई.सी. (1300 मिली। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में) बुवाई के तुरंत बाद, तत्पश्चात् बुवाई के 20 से 25 दिन बाद विस्पायरीवैक सोडियम 10 एस.एल. (80 मिली। प्रति एकड़) या पायराइजो सल्यूरान (80 मिली। प्रति एकड़) को 120 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 10-20 दिनों के बाद, मात्रा 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव करें या मेटालाक्लोर 50 ई.सी. फसल बुवाई के दो दिन के अंदर मात्रा-2.0 लीटर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना उचित होगा।

कृषि विभाग उ.प्र. द्वारा संचालित समस्त कृषि रक्षा इकाइयों पर फसलों के लिए उपयुक्त कृषि रक्षा रसायन/खरपतवारनाशी 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध हैं। किसानों से अनुरोध है कि खरीफ फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण कर अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाएँ। यदि कोई समस्या हो तो सहयोग हेतु नजदीकी कृषि रक्षा इकाइयों से संपर्क स्थापित कर समस्या का समाधान प्राप्त करें।

मात्रा-1.60 लीटर/हेक्टेयर।

पाइराजोसल्यूरान इथाइल 10 प्रतिशत, डब्ल्यू.पी.-0.15 किग्रा।

विस्पायरीवैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. 0.20 लीटर रोपाई के 15-20 दिन बाद नमी की स्थिति में।

2. मक्का फसल

मक्का में एक वर्षीय घासकुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हेतु एट्राजीन 2.0 किग्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई के तुरंत बाद या जमाव से पूर्व दो दिनों में 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव करें।

3. अरहर

अरहर में बुवाई के तुरंत बाद पेडीमिथालीन 30 ई.सी. 2.5 से 3.0 लीटर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव करें या इमैजीथापर 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर बुवाई के 15-25 दिन बाद छिड़काव करें।

4. उर्द/मूंग

उर्द/मूंग में खरपतवार नियंत्रण हेतु इमैजापायर 10 ई.सी. पानी में मिलाकर बुवाई के 10-20 दिनों के बाद, मात्रा 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव करें या मेटालाक्लोर 50 ई.सी. फसल बुवाई के दो दिन के अंदर मात्रा-2.0 लीटर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना उचित होगा।

उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे उपयुक्त जगह है

लखनऊ। लखनऊ। एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित करने हेतु समाधान विषय पर एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन के विषयगत सत्र में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिरकत करते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड लोकेशन बना है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सभी कारकों में बेहतरी आई है, प्रदेश में आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कानून व्यवस्था सड़क के ला एंड आर्डर मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने बैंकिंग से जुड़े प्रतिनिधियों से एमएसएमई के लिए राह आसान करने की आवश्यकता भी जताई।

उन्होंने कहा है सरकार के प्रयास तभी फलीभूत होंगे, जब सरकारी बैंक भी इस सेक्टर के लिए उदार बनेंगे। वित्त मंत्री ने सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सत्ता में आते योगी सरकार ने ओडीओपी, यूनिटी माल, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आदि के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने इसकी रफ्तार को बढ़ाने को कहा। उन्होंने बैंकों से भरोसा जताया कि वह मदद करने की मंशा से इन उद्योगों को सहारा देने का काम करें तभी प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर इकानामी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है

लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन, लखनऊ में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को यूरिया, डीएपी एवं एनपीके उर्वरकों की बिक्री निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही सुनिश्चित कराई जायेगी। किसी भी दशा में किसानों को ऊँची कीमत पर उर्वरक बेचने या अन्य उत्पादों की अनिवार्य टैगिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्येक बिक्री पर रसीद उपलब्ध कराई जायेगी और अगर कोई थोक या फुटकर विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्री शाही ने मीडिया को बताया कि अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं से सटे जनपदों में उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री पर विशेष सतर्कता बरती जायेगी। उर्वरक वितरण में कालाबाजारी या अनियमितता की कोई भी सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिनांक 23 जून 2025 को सीतापुर और लखनऊ में उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। उनके साथ अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) टी.एम. त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक) आशुतोष मिश्रा सहित कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सीतापुर जनपद में प्रमुख कार्यवाहियां का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि जैन इंटरप्राइजेज, सीतापुर : स्टाक में गड़बड़ी, गलत रजिस्टरिंग, रिटेलर्स को कम मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराना एवं टैगिंग पाई गई। प्रतिष्ठान को तत्काल सील कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। श्री बालाजी एग्रो ट्रेडर्स, जेल रोड, सीतापुररू स्टाक का मिलान सही नहीं पाया गया, प्रतिष्ठान सील किया गया। आगे की जांच उपजिलाधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। बालाजी ट्रेडर्स, सिधौली : स्टाक व बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए गए, रेट बोर्ड भी नहीं लगा था। कृषकों के बयान लिए जाएंगे। अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अन्य प्रतिष्ठानों-ए.एन.वी. एग्रो एण्ड कैमिकल्स, न्यू अय्यूब खाद भण्डार, न्यू अंसारी खाद भण्डार एवं तराई बीज भण्डार के प्रतिष्ठानों को प्रतिनिधि के मौके से भागने और अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण सील कर दिया गया।

कृषि मंत्री ने बताया कि लखनऊ में अनियमितताओं पर सीधी कार्रवाई की गयी है। किसान खाद भण्डार, बेहटा, कुर्सी रोड कृषकों को निर्धारित दर 266.50 रू. प्रति बैग से अधिक दर पर यूरिया बेचा गया। थोक विक्रेता ओम प्रकाश एवं जय प्रकाश द्वारा फुटकर विक्रेताओं को 300 रू. प्रति बैग की दर से यूरिया बेचने की पुष्टि हुई। दोनों के लाइसेंस निलंबित कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पाल खाद भण्डार, कल्याणपुर बिक्री रजिस्टर में कृषकों के विवरण अधूरे मिले। कई कृषकों से दूरभाष पर संपर्क किया गया, जिनमें कई मोबाइल नंबर गलत या बंद पाए गए। प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र ने दिए सख्त निर्देश

खरीफ सीजन में किसानों को मिलेगी पर्याप्त मात्रा में खाद

-निजी उर्वरक रैंक से 40 प्रतिशत आपूर्ति पीसीएफ को देने के निर्देश

लखनऊ। प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस क्रम में प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपदों में निजी उर्वरक कम्पनियों की उर्वरक रैंक से 40 प्रतिशत उर्वरकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सहकारी विपणन संघ (पीसीएफ) को कराई जाए।

उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सहकारी समितियों पर किसानों की बढ़ती मांग के अनुपात में पीसीएफ के पास उर्वरकों की उपलब्धता सीमित है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि निजी रैंक से 40 प्रतिशत उर्वरक सहकारी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाएं, जिससे कृषकों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

गत वर्ष भी इस उद्देश्य से शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत 50 प्रतिशत उर्वरकों की आपूर्ति पीसीएफ को कराई गई थी। इस बार खरीफ सीजन 2025 के लिए 40 प्रतिशत आपूर्ति का निर्णय कृषक हित में आवश्यक एवं समीचीन माना गया है।

प्रमुख सचिव कृषि ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि खाद वितरण की इस व्यवस्था को राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कृषकों तक पारदर्शी रूप से पहुँचाया जाए। जिलाधिकारी स्वयं मौके पर जाकर वितरण व्यवस्था की निगरानी करें एवं यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विक्रेता कालाबाजारी या ओवर रेटिंग न करे।

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को केवल उनके जोत/कृषि भूमि की आवश्यकता के अनुरूप और संस्तुत मात्रा में ही खाद क्रय करने की अनुमति दी जाए। साथ ही कृषकों को टीएसपी (ट्रिसुपर फास्फेट) एवं एनपीके(नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटाश) जैसे संतुलित उर्वरकों के प्रयोग हेतु जागरूक भी किया जाए।

प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसानों को समय पर और उचित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और राज्य में कृषि उत्पादन सतत रूप से चलता रहे।

प्रदेश में उच्च तकनीकी क्षमताओं के विकास का माध्यम बन रहा 'एआई प्रज्ञा'

■ कौशल विकास मिशन मुख्यालय में उत्पादक .त्रिम बुद्धिमत्ता व साइबर सुरक्षा पर अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

■ जनरेटिव एआई तथा साइबर सुरक्षा जैसे समसामयिक विषयों पर केंद्रित रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम, दक्षता बढ़ाने में बन रहा मददगार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए, बुधवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्यालय में "एआई प्रज्ञा" परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जनरेटिव एआई) तथा साइबर सुरक्षा जैसे समसामयिक विषयों पर केंद्रित रहा, जिसमें मिशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्रदान किया गया।

यह विशेष पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस दूर दृष्टिपूर्ण सोच का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश को डिजिटल भारत मिशन के अनुरूप आधुनिक तकनीकों से युक्त किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी अवधारणाओं के साथ-साथ उन्नत तकनीकी टूल्स तथा साइबर सुरक्षा तकनीकों की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही इन तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन (डेमान्स्ट्रेशन) भी प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक समझ विकसित करने में सहायता मिली। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि "एआई प्रज्ञा" परियोजना हम सभी के लिए एक अत्यंत उपयोगी अवसर है। इससे प्रदेश में उच्च तकनीकी क्षमताओं का विकास होगा और हमारे अधिकारी व प्रशिक्षणार्थी भविष्य की कार्य आवश्यकताओं के लिए और अधिक सक्षम बन सकेंगे। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विभाग की योजना है कि भविष्य में इसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों में भी संचालित किए जाएं, जिससे युवाओं की दक्षता में व्यापक वृद्धि हो सके।

कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के प्रतिनिधियों एवं माइक्रोसाट टीम के तकनीकी प्रतिनिधियों द्वारा साइबर सुरक्षा, डिजिटल व्यवहार, आनलाइन संचार के सुरक्षित उपयोग, वित्तीय लेन-देन तथा मोबाइल के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह, मिशन के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि, माइक्रोसाफ्ट टीम के सदस्य एवं बड़ी संख्या में विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) की शाखा खुलेगी, जिसके लिए 111 करोड़ रुपये स्वीकृत

अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आलू और शकरकंद की उन्नत किस्मों के विकास में मदद करेगा

लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के सरगना स्थित राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, लीमा (पेरू) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC) की स्थापना के प्रस्ताव को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना हेतु रू0 111 करोड़ की स्वी.ति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि यह ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 25 जून, 2025 को लिया गया, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र को कृषि अनुसंधान व तकनीकी नवाचार का लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि यह केंद्र आलू व शकरकंद की उन्नत, पोषणसमृद्ध और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन, और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण आयामों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होगा।

श्री सिंह ने कहा कि आलू की उत्पत्ति जिस देश पेरू में हुई, वहीं के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की यह शाखा अब उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित की जा रही है। एशिया में अब तक इसकी केवल एक शाखा चीन में है और दूसरी शाखा आगरा में खुलना उत्तर भारत और राज्य के किसानों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2300 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। आगरा और आसपास के क्षेत्रों में ही 1000 से अधिक कोल्ड स्टोरेज स्थित हैं, जो इस क्षेत्र को आलू उत्पादन और भंडारण का सबसे उपयुक्त केंद्र बनाते हैं। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग ने अपनी राजकीय आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र में से 25 एकड़ भूमि नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड को इस संस्थान हेतु दी है। वन विभाग और मंडी परिषद के सहयोग से सभी बाधाएं दूर कर स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और केंद्रीय कृषि मंत्री के समर्थन तथा वन एवं मंडी विभागों के सहयोग का आभार व्यक्त किया।

मंत्री ने बताया कि इस परियोजना को गति देने के उद्देश्य से अप्रैल 2025 में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी एवं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी.एल. मीणा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का भ्रमण कर व्यापक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से केंद्र की स्थापना में वैश्विक मापदंडों के अनुसार तकनीकी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की बागवानी की गई तथा 61.46 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 27 प्रतिशत है। सहारनपुर, मेरठ, बाराबंकी, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे जनपद प्रमुख आम उत्पादक हैं।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश से 40.31 मीट्रिक टन आम का अन्य देशों को निर्यात किया गया, जबकि वर्ष 2025 में अब तक 13.5 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया जा चुका है। आम महोत्सव के माध्यम से प्रदेश सरकार आम के उत्पादन, विपणन और निर्यात को नई दिशा देना चाहती है। महोत्सव में 600 से अधिक आम की किस्में, आम पकवान प्रतियोगिता, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण व कार्यशालाएं तथा सांस्कृतिक संध्या के रूप में कवि कुमार विश्वास का विशेष कार्यक्रम शामिल रहेगा। मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों के बागवान, निर्यातक व विभागीय प्रतिनिधि भी प्रतिभाग करेंगे।

मंत्री ने कहा कि आम और आलू दोनों उत्तर प्रदेश की पहचान हैं और इन क्षेत्रों में हो रहे नवाचार व निवेश प्रदेश के किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में सार्थक प्रयास हैं। यह हमारे विभाग को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मंत्री ने मीडिया से अनुरोध किया कि इस ऐतिहासिक निर्णय और आम महोत्सव की जानकारी अधिकाधिक किसानों व नागरिकों तक पहुँचाई जाए, जिससे वे इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 26 जनपद चिन्हित

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के कुल 26 जनपदों को चिन्हित किया है। इन जनपदों के अंतर्गत 47 ब्लॉक एवं 517 ग्रामों को शामिल किया गया है। चिन्हित जनपदों में आधार, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान लाभ, जनधन खाते, छात्रवृत्ति कवरेज एवं अन्य संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा किए जाने के लिए मिशन मोड के माध्यम से चलाया जाना है।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन जनपदों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, उनमें अंबेडकरनगर, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, बिजनौर, चन्दौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रयागराज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर एवं सोनभद्र शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजाति बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों जिनमें ग्राम्य विकास, जल जीवन मिशन (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), जल शक्ति, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एन.एच.एम.), खाद्य एवं रसद, महिला कल्याण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, आयुष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, पंचायती राज, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा संस्थागत वित्त विभाग शामिल हैं।